



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 283]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सं. 30/2015-2020

**विषय :** क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण-पत्र को जुर्माना दिए बिना स्वीकार किया जाना जिसमें संस्थापन प्रमाण पत्र 18 माह से आगे प्रस्तुत किया जाता है।

**फा. सं. 18/96/एम 19/पी-5.**—विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.58 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार जनहित में एतद्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने से संबंधित प्रक्रिया में एककालिक छूट प्रदान करते हैं:—

1. ईपीसीजी स्कीम के तहत, प्राधिकार पत्र धारकों को संस्थापन प्रमाण पत्र जिसमें पूंजीगत माल के संस्थापन को दर्शाया गया हो क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्धारित समयावधि के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
2. कभी-कभी क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाण पत्र मशीन के संस्थापन में विलम्ब/संस्थापन प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब आदि सहित विभिन्न कारणों से निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं हुआ। ईपीसीजी समिति को क्षेत्रीय प्राधिकारियों को संस्थापन प्रमाण पत्र जमा करने की समयावधि में माफी के अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। 5000/रु. के संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर ईपीसीजी समिति द्वारा माफी के कुछ ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया गया।
3. एक सुविधाजनक उपाय के रूप में दिनांक 25.10.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015-20 जारी की गई जिसमें 5000/— रु. प्रति प्राधिकार पत्र (बशर्त संस्थापन 18 महीने की अवधि के भीतर हुआ है) जुर्माना का भुगतान करने पर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी देते हुए दिनांक 31.03.2018 तक की समयावधि के लिए माफी हेतु एक कालिक छूट की अनुमति प्रदान की गई। उक्त सार्वजनिक सूचना का लाभ दिनांक 26.04.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-20 के द्वारा 30.09.2018 तक बढ़ाया गया।
4. यदि संस्थापन निर्धारित विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हुआ है तो जुर्माना मांगे बिना संस्थापन प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए व्यापार जगत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में यह तर्क है कि एचबीपी (2009-14) के पैरा 5.3.1 के बारे में उनकी समझ के अनुसार संस्थापन प्रमाण पत्र जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है और समय सीमा केवल मशीनरी के संस्थापन के लिए थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि विगत में कुछ क्षेत्रीय प्राधिकारियों ने मोचन के

समय में भी संस्थापन प्रमाण पत्र स्वीकार किए हैं। इसलिए, इन प्राधिकार पत्रों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाने का अनुरोध किया गया है।

5. मामले पर विचार किया गया है। संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना ईपीसीजी स्कीम की निगरानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे निर्यात दायित्व अवधि के पूरा होने तक टाला नहीं जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा का स्पष्ट रूप से यह आशय था कि पूंजीगत माल का आयात किया जाए, संस्थापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और उक्त पैरा की समयावधि के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। ईपीसीजी स्कीम हेतु संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना को पढ़ने से भी यह स्पष्ट होता है कि संस्थापन प्रमाण पत्र को विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया गया है कि वे प्रक्रिया पुस्तक (2009-14) के अंतर्गत पैरा की इस तरह व्याख्या कर सकते हैं कि समयावधि केवल संस्थापन/प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लागू होती है तथा वे इसे क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी भी समय, यहां तक कि मोचन के समय पर भी उपलब्ध करा सकते हैं।
6. इस संबंध में अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए तथा इस प्रयोजन हेतु व्यापार करने को सुगम बनाने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी को 31.03.2015 तक जारी प्राधिकार-पत्र के संबंध में जुर्माने पर न जोर देते हुए संस्थापन प्रमाण-पत्र को स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है यदि आयात की तिथि से 18 माह के अंदर संस्थापन हो गया हो, बशर्ते ईपीसीजी प्राधिकार पत्र किसी अन्वेषण के अधीन न हों या क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी/किसी अन्य अन्वेषण एजेंसी द्वारा अधिनिर्णित न हो। यह छूट 31.03.2019 तक उपलब्ध होगी। सार्वजनिक सूचना सं० 37/2015-20, दिनांक 25.10.2017 के तहत पहले से भुगतान किए गए जुर्माने का कोई रिफंड नहीं होगा।
7. इस सार्वजनिक सूचना के सुसंगत सार्वजनिक सूचना सं. 37/2015-20, दिनांक 25.10.2017 और सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-20, दिनांक 26.04.2018 के अन्य नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** दिनांक 31.03.2015 तक जारी किए गए प्राधिकार-पत्र हेतु ईपीसीजी स्कीम के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी और एक कालिक छूट बिना किसी जुर्माने के भुगतान के दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th August, 2018

No. 30/2015-20

**Subject : Acceptance of installation certificate under EPCG Scheme by the RAs, wherein installation certificate is submitted beyond 18 months, without penalty**

**F. No. 18/96/AM-19/P-5.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of FTP (2015-20) read with Paragraph 2.58 of FTP (2015-20), the Director General of Foreign Trade in public interest hereby makes the one time relaxation in procedure in respect of acceptance of installation certificate under the EPCG Scheme.

1. Under the EPCG Scheme, the authorization holders are required to submit the installation certificate showing installation of the capital goods to the RA within the prescribed time period.
2. Sometimes, the submission of installation certificate to the RAs was not within the time prescribed on account of various reasons, including delay in installation of the machinery/delay in issuance of installation certificate etc. The EPCG Committee was receiving requests for condonation of time period of submission of installation certificate to the Regional authorities. Some of such requests for condonation were considered by the EPCG Committee on payment of composition fee of Rs.5,000/-
3. As a facilitative measure, Public Notice No.37/2015-20 dated 25.10.2017 was issued permitting one time relaxation for condonation of time period upto 31.03.2018 condoning the delay in submission of installation certificate on payment of penalty of Rs.5000/- per authorization (provided the installation has happened within the period of 18 months). The benefit of said Public Notice was further extended upto 30.09.2018 vide Public Notice No.01/2015-20 dated 26.04.2018.
4. There have been representations from the Trade for accepting the submission of installation certificate without insisting on penalty, if the installation has happened within the specified time prescribed. The

contention in the representations is that as per their understanding, of the para 5.3.1 of HBP (2009-14), there was no time limit for submission of the installation certificate and the time limit was only for the installation of machinery. It has also been pointed out that in the past, some RAs have accepted the installation certificate even at the time of redemption. Therefore, it has been requested not to impose any penalty for these authorizations.

5. The issue has been considered. The submission of installation certificate is an important aspect of monitoring of the EPCG Scheme which cannot be postponed till the completion of the EO period. The intent of the para of the HBP was clearly that the capital goods were to be imported, the installation certificate obtained and presented to the RAs within the time period in the said para. The reading of the relevant custom notification for the EPCG Scheme also makes it clear that the installation certificate was to be produced within the period specified. However, it is contended by some that they could interpret the para under the HBP (2009-14) that the period applies only for installation/obtaining the certificate and they can provide the same to the RAs anytime even at the time of redemption.

6. Taking into account the representations in this regard and to facilitate the ease of doing business for the purpose, it has been decided to permit the RAs to accept the installation certificate without insisting for penalty in respect of authorization issued upto 31.03.2015 as long as the installation has happened within 18 months from the date of import, provided the EPCG authorization is not under any investigation/adjudicated by RA/customs authority/any other investigative agency. This relaxation will be available upto 31.03.2019. There will not be any refund of the penalty already paid under the Public Notice No.37/2015-20 dated 25.10.2017.

7. The other terms and conditions in the Public Notice No.37/2015-20 dated 25.10.2017 and Public Notice No.01/2015-20 dated 26.04.2018 consistent with this Public Notice will continue to be applicable.

**Effect of this Public Notice :** One time relaxation and condonation of delay in submission of installation certificate to RAs under EPCG Scheme for authorizations issued upto 31.03.2015, without payment of any penalty.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade